गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 147
दि. 26.09.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति ने वृंदावन और मथुरा का दौरा किया

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (25 सितंबर, 2025) एक विशेष ट्रेन से नई दिल्ली से वृंदावन (उत्तर प्रदेश) की यात्रा की।

अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान, उन्होंने वृंदावन और मथुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया। राष्ट्रपति ने श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, सुदामा कुटी, कुब्जा कृष्ण मंदिर और श्री कृष्ण जन्मस्थान में

प्रधानमंत्री आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे

योजना का उद्देश्य स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है

योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं को सीधे 7500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे

प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये के प्रारंभिक हस्तांतरण के साथ, बाद में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गुंजाइश होगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये, यानी कुल 7,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे।

बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी

पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं, इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और अन्य लघु-स्तरीय उद्यम शामिल हैं।

यह योजना समुदाय-संचालित होगी और इसमें वित्तीय सहायता के साथ-साथ, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उनके प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और ओईएम सलाहकार समिति के साथ बैठक की अध्यक्षता की

आईएमसी 2025 की योजना, टीएसपी और ओईएम मुद्दों, तथा ग्वालियर स्थित दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र और जबलपुर स्थित दूरसंचार नवाचार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की प्रगति की समीक्षा

(जीएनएस)।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दूरसंचार सचिव डॉ. नीरज मित्तल के साथ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और मूल उपकरण निमार्ताओं (ओईएम) सलाहकार समिति के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में तीन प्रमुख एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया - इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 की तैयारियों की समीक्षा, टीएसपी और ओईएम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा, और ग्वालियर में दूरसंचार विनिर्माण

क्षेत्र (टीएमजेड) और जबलपुर में दूरसंचार नवाचार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थिति का आकलन।

विचार-विमर्श के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पहले उठाए गए अधिकांश लंबित मुद्दों, विशेष रूप से साइबर सुरक्षा, स्पैम नियंत्रण, मानकों और प्रौद्योगिकी अंतर-संचालनीयता से संबंधित, का समाधान कर लिया गया है। तीन महत्वपूर्ण मुद्दे - डिजिटल डिवाइड, स्पेक्ट्रम प्राधिकरण और फिक्स्ड-लाइन सेवाओं की व्यावसायिक व्यवहार्यता, अभी भी विचाराधीन हैं, और हितधारकों से 6 अक्टूबर 2025 तक मसौदा नियमों पर प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा की जाती है। आगामी दूरसंचार नीति ढाँचे के तहत टेलीमार्केटर नियमों, लाइसेंस शुल्क और बिजली आवश्यकताओं से संबंधित मामलों पर भी विचार किया जा रहा है।

उपराष्ट्रपति की आंध्र प्रदेश की दो दिवसीय यात्रा संपन्न हुई

श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने विजयवाड़ा उत्सव में भाग लिया और कनक दुर्गा तथा तिरुमला मंदिरों में पूजा-अर्चना की

तिरुमला में नए तीर्थयात्री सुविधा केंद्र 'वेंकटाद्रि निलयम' का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने 24 और 25 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश की दो दिवसीय यात्रा की और विजयवाड़ा तथा तिरुमला में कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया।

उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद यह किसी राज्य की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने 24 सितंबर को विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन के साथ अपनी राजकीय यात्रा की शुरूआत की, जहाँ उन्होंने राष्ट्र की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बाद में, उन्होंने पुन्नामी घाट पर आयोजित विजयवाड़ा उत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति ने नारी देवत्व और महिला सशक्तिकरण के उत्सव के रूप में नवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि की प्रशंसा की और कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और समावेशी विकास में राज्य की उपलब्धियों की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा के लोगों के उत्साह और भावना की सराहना की।

(माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन विजयवाड़ा उत्सव में भाग लेते हुए।)

25 सितंबर को, श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने पवित्र तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और सभी नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की। बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) में नवनिर्मित तीर्थयात्री सुविधा केंद्र (पीएसी) 'वेंकटाद्रि निलयम' का उद्घाटन किया।

(माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हुए, सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए।)

'वेंकटाद्रि निलयम' एक पाँच मंजिला आधुनिक सुविधा केंद्र है, जिसे प्रतिदिन मंदिर आने वाले हजारों भक्तों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है।

प्रत्येक मंजिल में छह विशाल हॉल हैं, जिनमें उद्घाटन किए गए स्तर में चार शयनगृह और दो बाल मुंडन हॉल हैं। भवन में कुल 600 लॉकर लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक शयनगृह में 150 लॉकर भक्तों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। विभिन्न मंजिलों पर सुगम आवागमन के लिए परिसर में दस लिफ्ट और छह सीढ़ियाँ हैं।

सिक्किम के बागवानी महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन और वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन

सिक्किम अद्भुत प्रदेश, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर- श्री शिवराज सिंह

सिक्किम के किसान भाई-बहन केमिकल फर्टिलाइजर रहित शुद्ध उत्पाद पूरे देश में पहुंचा रहे हैं- श्री शिवराज सिंह

गैर-परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के कारण सिक्किम की बागवानी गतिविधियों में बहुत विविधता आई है- श्री चौहान

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है, पर्वतीय राज्यों को प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत सिक्किम के बर्मीओक स्थित बागवानी महाविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक भवन और वार्षिक क्षेत्रीय कार्यशाला का वर्चुअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी, सिक्किम के कृषि मंत्री श्री पूरन कुमार गुरुंग, कुलपति डॉ. अनुपम मिश्रा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भले ही आज मैं सशरीर सिक्किम में मौजूद नहीं हूं लेकिन मेरी अंतरात्मा बर्मिओक के बागवानी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में आपके बीच ही है। भारत सरकार के प्रतिनिधि के नाते श्री भागीरथ चौधरी वहां उपस्थित हैं। श्री चौहान ने कहा कि नवनिर्मित भवन का निर्माण 52 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। इसके निर्माण से सिक्किम के हमारे बेटे-बेटियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि सिक्किम अद्भुत प्रदेश है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सिक्किम की जलवायु अद्भुत है। सिक्किम की धरती पर एवोकाडो, कीवी, बड़ी इलायची, आर्किड सहित सब्जियों में अदरक, हल्दी, टमाटर और गोभियों की व्यापक संभावनाएं हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, बांस, औषधीय पौधों की रोपण जैसी गैर-परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के कारण सिक्किम की बागवानी गतिविधियों में बहुत विविधता आई है। उन्होंने कहा कि सिक्किम एक जैविक राज्य है। केमिकल फर्टिलाइजर से दूर शुद्ध उत्पाद यहां के किसान सिक्किम ही नहीं, पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहां के किसान भाई-बहनों को प्रणाम करता हूं।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खेती तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे पर्वतीय राज्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में खेती को आगे बढ़ाने में भारत सरकार अपनी ओर से कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। यहां की अनुपम जलवायु के कारण सिक्किम की जो विशेषताएं हैं, उनका कैसे हम और ज्यादा दोहन कर पाएं, इसकी हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जैविक उत्पादन बढ़ रहा है और यह आज की जरूरत भी है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 6 सूत्र हैं। इसमें उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। इसके साथ ही कृषि का विविधीकरण। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती, बांस की खेती, बागवानी में किसानों की आय में वृद्धि करने की संभावना है। इसके साथ ही श्री चौहान ने कहा कि एक चिंता यह है कि हम कैसे जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग के कारण अनेकों प्रकार के रोगों को हमने एक प्रकार से

प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की वैचारिक और विकास यात्रा में उनके अप्रतिम योगदान का स्मरण किया। पीएम ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंतिम पायदान पर उपस्थित व्यक्ति के उत्थान से जुड़ा उनका एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय का दृष्टिकोण भारत के विकास मॉडल को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में पूर्ण रूप से समाहित हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहाः 'भारत माता के महान सपूत और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन।

आयुष मंत्रालय ने संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस शिखर सम्मेलन का विषय होगाः "लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करनाः कल्याण का विज्ञान और अभ्यास"।

शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

आगामी शिखर सम्मेलन की गतिविधियों और प्रगति की निगरानी के लिए आयोजित द्वितीय शिखर सम्मेलन योजना समूह की बैठक के दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव और आयुष मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य

यह वैश्विक शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों, नीति निमार्ताओं और हितधारकों को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन के साथ साझेदारी में साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो मानव और ग्रह के कल्याण में योगदान देती हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवरात्रि के चौथे दिन अहमदाबाद में नगरदेवी श्री भद्रकाली माताजी के दर्शन कर स्वच्छता अभियान के तहत महा श्रमदान में शामिल हुए

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 25 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गुरुवार को अहमदाबाद की नगर देवी श्री भद्रकाली माताजी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत आयोजित किए गए महा श्रमदान में सहभागी हुए और भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में साफ-सफाई की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर-2025 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत राज्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का आयोजन किया गया है।

स्वच्छता ही सेवा-2025 अभियान के अंतर्गत अब तक अहमदाबाद शहर में 2.97 लाख से अधिक नागरिक स्वैच्छिक रूप से स्वच्छता की गतिविधियों में शामिल हुए हैं।

अभियान के तहत 1877 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। इसके अलावा, शहर की लगभग 5495 मुख्य सड़कों, 3677 वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा 3229 से अधिक रिहायशी इलाकों की साफ-सफाई भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने भद्रकाली मंदिर क्षेत्र में सफाई श्रमदान के दौरान राहे खेर गर्ल्स हाईस्कूल, खमासा की छात्राओं से मुलाकात की और उनके द्वारा स्वच्छता पर तैयार किए गए चित्रों का अवलोकन किया। उन्होंने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश इसी प्रकार जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर अनुपम ब्रिज के पास उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक सर्वश्री अमितभाई ठाकर, कौशिकभाई जैन, अमूलभआई भट्ट, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, दिनेशभाई कुशवाह, जीतूभाई पटेल, शहर के अग्रणी श्री प्रेरकभाई शाह और श्री भूषणभाई भट्ट, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी और अधिकारियों सहित नागरिक उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

हिंसा व रौद्र रूप दिखाता अक्सर शांत रहता लेह

लद्दाख शांत और अहिंसा परमो धर्मः के प्रति निष्ठावान नागरिकों की जन्मस्थली और कर्म स्थली रही है किन्तु बुधवार को जिस तरह लेह में वहां के लोगों ने रौद्र रूप दिखाते हुए बवाल किया। जिसमें सीआरपीएफ के वाहन, पुलिस के वाहन, भारतीय जनता पाटा हिल कौंसिल के कार्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों को जला डाला। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हुई और 80 लोग घायल हुए। उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अकेले सोनम वांगचुक ने न तो इस आंदोलन को हिसक बनाया और न ही लद्दाख के आम लोगों ने इस आंदोलन की परिणति को बारूदी बनाया। हिंसा की आग दूसरे दिन भी धधकती रही परिणामस्वरूप पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने वेंद्र शासित प्रादेश में लगे कर्फ्यू का पालन कराने के लिए 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है।

दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर जारी आंदोलन के हिसक रूप लेने के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 15 दिनों से जारी अपनी भूख हड़ताल को बुधवार के दिन ही समाप्त कर दिया था। लगता है कि वांगचुक को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी भूख हड़ताल का उद्देश्य अब भटक चुका है। वैसे तो कारगिल डेमोव्रेटिक अलायंस (केडीए) लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) द्वारा वांगचुक के समर्थन में बंद का आ'ान किया गया था। लेकिन हर आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी प्राभावशाली नेतृत्व के अभाव में भटक गया और स्वाथा चाण्डाल चौकड़ी हिसा पर उतारू हो गईं। सच तो यह है कि 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर की ही तरह लद्दाख को भी वेंद्र शासित प्रादेश घोषित कर दिया गया था। अब लद्दाख में राजनेताओं को लग रहा है कि यदि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हो जाए तो उनके राजनीतिक करियर के लिए अवसर मिल जाएगा। किन्तु वेंद्र सरकार अच्छी तरह समझती है कि लद्दाख सीमावता वेंद्र शासित प्रादेश राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील होने के कारण उसके बारे में कोई भी पैसला भावनाओं के आधार पर लेना नासमझी होगी। जिन लोगों ने आंदोलन को हिसक बनाया वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लद्दाख में अशांति के समर्थक पाकिस्तान और चीन भी हैं। भारत सरकार ने पिछले वुछ दिनों से लद्दाख में जितना ढांचागत विकास किया है, उससे दोनों ही शत्रु देशों के होश उड़े हैं। ये दोनों चाहते हैं कि लद्दाख किसी न किसी रूप में अशांत हो। चीन के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि उसने लद्दाख के वुछ नेताओं को आर्थिक मदद भी दी है। यदि यह सही है तो इससे हैरानी नहीं होनी चाहिए। 1957 से चीन ने पूवरेत्तर राज्यों में सशस्त्र विरोध के लिए अलगाववादी संगठनों का गठन किया फिर उन को धन और हथियार देकर हिसक विद्रोह के लिए भड़काया था। तत्कालीन प्राधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू चीन को अपना भाईं मानते थे किन्तु जब इंटेलीजेंस ब्यूरो ने उनको चीन की हरकतों के बारे में सूचना दी तो वे खुद ही पूवरेत्तर राज्यों के दौरे पर गए और भावनात्मक अपील करते हुए लोगों से कहा था कि यहां की समस्या आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव की नहीं है। "मैं तो अगले जन्म में आदिवासी परिवार में जन्म लेना चाहूंगा क्योंकि आदिवासी परिवार के लोग पवित्र हृदय के होते हैं।" पंडित नेहरू की भावनात्मक अपील का कोई असर नहीं हुआ। बाद में इंदिराजी ने पूवरेत्तर के राज्यों में शांति के लिए राजनीतिक प्रायास किया। स्वगाय राजीव गांधी ने भी मिजोरम को शांत करने के लिए मिजो नेशनल प्रांट के साथ समझौता किया। रही सही समस्याओं को मौजूदा सरकार ने हल किया। लद्दाख में पूर्ण राज्य का मुद्दा गरमाया हुआ है किन्तु इंटेलीजेंस एजेंसियां इसे गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं हैं। हमारी आईबी, मिलिट्री इंटेलीजेंस और बीएसएफ इंटेलीजेंस कश्मीर में ही सक्रिय रहती हैं, वे लद्दाख में सक्रियता से काम नहीं कर पाईं अन्यथा इतना बड़ा बवाल न होता। बहरहाल, सरकार लद्दाख को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती। इसलिए बहुत गंभीरता से वहां के लोगों को समझाने-बुझाने तथा शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाईं करके उन्हें स्टेट अथारिटी का एहसास कराने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया

हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा मिशन को जन आंदोलन में बदल रही है: प्रधानमंत्री

हम समाज के प्रत येक वर्ग के कल्याण के लिए सेवा भावना से कार्य कर रहे हैं: प्रधानमंत्री

यह सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है कि जनजातीय समुदाय सम्मान और आत्मसम्मान से निर्वाह करे : प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 1,22,100 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नवरात्रि के चौथे दिन, प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में माँ त्रिपुरा सुंदरी की पावन धरती पर आने को अपना सौभाग्य कहा। उन्होंने बताया कि उन्हें कांठल और वागड़ की गंगा कही जाने वाली माँ माही के दर्शन करने का भी अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि माही का जल भारत के जनजातीय समुदायों के लचीलेपन और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने महायोगी गोविंद गुरु जी के प्रेरक नेतृत्व पर प्रकाश डाला, जिनकी विरासत आज भी गूंजती है और माही का पवित्र जल उस महान गाथा का साक्षी है। श्री मोदी ने माँ त्रिपुरा सुंदरी और माँ माही को नमन किया और भक्ति एवं वीरता की इस भूमि से उन्होंने महाराणा प्रताप और राजा बांसिया भील को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

श्री मोदी ने कहा कि नवरात्रि के दौरान, देश में शक्ति के नौ रूपों की पूजा की जाती है, और बांसवाड़ा में आज का प्रमुख कार्यक्रम ऊर्जा शक्ति - ऊर्जा उत्पादन को समर्पित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान की धरती से भारत के बिजली क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली परियोजनाओं के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का एक साथ आरंभ होना ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तेजी से हो रही प्रगति की झलक दिखाता है, जिसमें देश का हर क्षेत्र सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और सभी राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और पारेषण लाइनों की आधारशिला रखी गई है। श्री मोदी ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सौर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक, भारत बिजली उत्पादन क्षमता में नई ऊँचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज के तकनीक और उद्योग के युग में, विकास बिजली की शक्ति पर निर्भर करता है; बिजली प्रकाश, गति, प्रगति, संपर्क और वैश्विक पहुँच लाती है।" उन्होंने बिजली के महत्व की उपेक्षा करने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। श्री मोदी ने कहा कि जब 2014 में उनकी सरकार सत्ता में आई थी, तब 2.5 करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे और आजादी के 70 साल बाद भी, 18,000 गाँवों में एक भी बिजली का खंभा नहीं लगा था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बड़े शहरों में घंटों बिजली कटौती होती थी और गाँवों में तो 4-5 घंटे बिजली भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बिजली की अनुपस्थिति ने कारखानों के संचालन और नए उद्योगों की स्थापना में बाधा डाली, जिसका असर राजस्थान जैसे राज्यों और पूरे देश पर पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि हर गाँव तक बिजली पहुँचाई गई और 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त कनेक्शन दिए गए। जहाँ भी बिजली की लाइनें पहुँचीं, वहाँ बिजली पहुँची—जिससे जीवन आसान हुआ और नए उद्योगों का विकास संभव हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश को 21वीं सदी में तेजी से विकास करने के लिए, अपने बिजली उत्पादन को बढ़ाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे सफल देश वे होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना की शुरूआत की घोषणा करते हुए जोर देकर कहा, "हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा मिशन को एक जन आंदोलन में बदल रही है।" इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं। किसानों को सस्ती बिजली सुनिश्चित करने के लिए, पीएम-कुसुम योजना कृषि क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न राज्यों में अनेक सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिससे लाखों किसानों को सीधे लाभ हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि पीएम सूर्य घर योजना घरों के लिए मुफ़्त बिजली प्रदान करती है, जबकि पीएम-कुसुम योजना खेतों के लिए मुफ़्त बिजली सुनिश्चित करती है। श्री मोदी ने पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ अपनी पिछली बातचीत साझा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाली मुफ़्त बिजली उनके जीवन में एक बड़ा वरदान बन गई है।

श्री मोदी ने कहा, "भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और राजस्थान इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।" उन्होंने राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की शुरूआत की घोषणा की, जिनका उद्देश्य पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत सेवा सहित तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने नए रोजगार के अवसर पैदा करने के राष्ट्रव्यापी अभियान पर प्रकाश डाला, जिसके तहत आज राजस्थान में 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र मिले। श्री मोदी ने इन युवाओं को अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरूआत के लिए शुभकामनाएँ दीं और इन विकास पहलों के शुभारंभ पर राजस्थान के लोगों को बधाई दी।

राजस्थान में उनकी सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा कुशासन और शोषण के माध्यम से राजस्थान को दिए गए घाव अब वर्तमान सरकार द्वारा भरे जा रहे हैं। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के शासन में, राजस्थान पेपर लीक का केन्द्र बन गया था और जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर थे और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विपक्ष के कार्यकाल के दौरान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्रों में अपराध और अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि देखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जनता ने उन्हें मौका दिया, तो कानून-व्यवस्था मजबूत हुई और विकास की गति तेज हुई। उन्होंने कहा कि अब बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और पूरे राजस्थान में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जाल फैल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान, विशेषकर दक्षिणी राजस्थान को विकास के तीव्र पथ पर अग्रसर कर रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने देश को अंत्योदय का सिद्धांत दिया - समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान - श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कल्पना अब सरकार का मिशन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन गरीबों, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए गहरी सेवा भावना से काम कर रहा है।

आदिवासी समुदाय की लगातार उपेक्षा और उनकी जरूरतों को समझने में नाकाम रहने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने ही एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना करके जनजातीय कल्याण को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार जनजातीय मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के शासन में, इतने बड़े पैमाने की परियोजनाओं का जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचना अकल्पनीय था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के तहत, ये विकास अब हकीकत बन रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के धार में एक बड़े पीएम मित्र पार्क के शुभारंभ की घोषणा की, जिससे आदिवासी किसानों को सार्थक लाभ होगा।

श्री मोदी ने उल्लेख किया कि उनकी पार्टी के प्रयासों से ही एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं सबसे हाशिए पर पड़े जनजातीय समुदायों का मुद्दा उठाया था, जिससे प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू करने की प्रेरणा मिली। इस पहल के तहत, जनजातीय समाज के सबसे वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से आदिवासी गाँवों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे पाँच करोड़ से ज्यादा आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में सैकड़ों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को भी मान्यता दी है।

श्री मोदी ने कहा, "भारत का जनजातीय समुदाय हजारों वर्षों से वन संसाधनों का निरन्तर उपयोग करता आ रहा है।" यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये संसाधन उनकी प्रगति का साधन बनें, सरकार ने वन धन योजना शुरू की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वन उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है और आदिवासी उत्पादों को बाजार तक पहुँच से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, भारत में देश भर में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है।

आदिवासी समुदाय के सम्मान के साथ जीवन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी आस्था, स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना एक गंभीर संकल्प है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब एक आम नागरिक का जीवन आसान हो जाता है, तो वे स्वयं राष्ट्र की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने 11 साल पहले विपक्ष के शासन के दौरान की भयावह परिस्थितियों को याद किया और इसके लिए नागरिकों के शोषण और व्यवस्थित लूट को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि उस दौरान कर और मुद्रास्फीति रिकॉर्ड ऊँचाई पर थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार जनता ने उनकी सरकार को आशीर्वाद दे दिया, तो विपक्ष की शोषणकारी कार्य प्रणाली का अंत हो गया।

श्री मोदी ने कहा कि 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन ने देश को करों और टोल के जटिल जाल से मुक्ति दिलाई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष नवरात्रि के पहले दिन, एक बड़ा जीएसटी सुधार लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे भारत में जीएसटी बचत उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें अब ज्यादा सस्ती हो गई हैं। उपस्थित महिलाओं की विशाल सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा कि घरेलू रसोई का खर्च काफी कम हो गया है, जिससे देश भर की माताओं और बहनों को सीधी राहत मिली है।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत 'एक दिन एक घंटा एक साथ' अभियान में शामिल हुआ, पूरे परिसर में स्वच्छता में चैंपियन बना

(जीएनएस)।

स्वच्छ राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का एक उत्साही पहल करते हुए आयुष मंत्रालय के भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) ने व्यापक स्वच्छता ही सेवा - 2025 अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक पहल "एक दिन एक घंटा एक साथ" कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल और उसके आसपास स्वच्छता, सफाई और अनुशासन की एक सतत संस्कृति को बढ़ावा देना है, और इस बात पर बल देना है कि सामूहिक कार्रवाई की शक्ति ही सार्थक बदलाव ला सकती है। इस वर्ष की थीम विशेष रूप से देश के उत्सवों की उल्लासमय भावना को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के लिए तैयार की गई है।

अभियान के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग ने अपने परिसर और आसपास के आवासीय क्षेत्रों में एक विशाल रैली और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। कर्मचारियों ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग परिसर के पॉकेट 1 से पॉकेट 3 तक, साथ ही परिसर से सटे आसपास के

इलाकों में भी सफाई अभियान चलाया।

कार्यक्रम के दौरान, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग के निदेशक ने कर्मचारियों को संबोधित किया और कार्यस्थल के अंदर और समुदाय में स्वच्छता और सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। निदेशक ने कर्मचारियों को अपने आस-पास के वातावरण की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया और यह भी बताया कि स्वच्छ भारत के व्यापक लक्ष्य को साकार करने के लिए टीम वर्क और सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

अभियान के माहौल को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग ने कर्मचारियों के उत्साह और भागीदारी को दशार्ने के लिए एक सेल्फी कॉर्नर की भी व्यवस्था की। ऐसा करके सहकर्मियों, मित्रों और आम जनता के साथ स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साझा करने की सहूलियत प्रदान की गई।

कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि संस्थागत समर्थन और शीर्ष-स्तरीय पहल महत्वपूर्ण हैं और सच्चा परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति के निरंतर प्रयासों में निहित है। भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज संहिता आयोग स्वच्छता को एक आदतन अभ्यास बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और अपने सभी कर्मचारियों, आगंतुकों और आसपास के समुदायों को स्वच्छ और हरित जीवन को वास्तविक रूप से स्थायी बनाने में हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया

(जीएनएस)।

निर्वाचन आयोग ने पिछले छह महीनों में चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 29 महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने अपनी 30वीं पहल के अंतर्गत देरी को कम करने और स्पष्टता बढ़ाने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। (अनुलग्नक)

मतगणना प्रक्रिया के दो प्रमुख भाग हैं:

डाक मतपत्रों/इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्रों (ईटीपीबी) की गिनती;

ईवीएम के माध्यम से गिनती।

मतगणना के दिन डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे और ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। पूर्व निदेशों के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती के चरण की परवाह किए बिना सैद्धांतिक रूप से ईवीएम की गिनती जारी रह सकती है और डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले इसके पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए घर से मतदान हेतु आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों के मद्देनजर डाक मतपत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यद्यपि डाक मतपत्रों की गिनती आमतौर पर ईवीएम की गिनती से पहले पूरी हो जाती है। फिर भी मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया है कि अब से ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले वाला (दूसरे अंतिम) दौर डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही मतगणना केंद्र पर शुरू किया जाएगा। जहाँ डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जहाँ डाक मतपत्रों की संख्या अधिक हो तो वहाँ रिटर्निंग अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त संख्या में टेबल और मतगणना कर्मचारी मौजूद हों ताकि कोई देरी न हो और मतगणना प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया जा सके।

पीके/ केसी/ एसके

अनुलग्नक

पिछले छह महीनों के दौरान 29 पहलों की सूची:

मतदाताओं की सुविधा

मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन सुविधा के वास्ते मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा सुविधा। (लिंक)

भीड़ कम करने के लिए प्रति मतदान केंद्र 1,200 से अधिक मतदाता नहीं। (लिंक)

मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) के डिजाइन को संशोधित किया गया है ताकि मतदाता का सीरियल नंबर और पार्ट नंबर अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित हो। (लिंक)

मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्र से 100 मीटर से थोड़ा आगे उम्मीदवार बूथों की अनुमति है। (लिंक)

बेहतर दृश्यता के लिए ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें होंगी। (लिंक)

चुनावी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण और सफाई

पंजीकरण की आवश्यक शर्तों को पूरा करने में लगातार विफल रहने वाले 808 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को दो चरणों में सूची से हटाया जाएगा। (लिंक)

संविधान आरपीए 1950, 1951 के अनुसार 28 ईसीआई हितधारकों की भूमिकाओं की पहचान और मानचित्रण। निर्वाचक नियम 1960 चुनाव संचालन नियम, 1961, और विभिन्न चुनाव आयोग निर्देश। (लिंक)

बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए। (लिंक)

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद ईवीएम की बर्न मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जाँच और सत्यापन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक मानक संचालन प्रक्रियाएँ। (लिंक)

ईसीआई के कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ और पुनर्निर्देशित करने हेतु कानूनी सलाहकारों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन। (लिंक)

दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें। (लिंक)

राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता

ईआरओ, डीईओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के स्तर पर देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। (लिंक)

अब तक 25 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठकें आयोजित की गईं। (लिंक)

प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग

ईसीआईएनईटी का शुभारंभ किया गया। यह मतदाताओं और अन्य के लिए 40 से अधिक ऐप/वेबसाइटों को समाहित करने वाला एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सभी हितधारकों के लिए। (लिंक)

मतदान प्रक्रिया की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग। (लिंक)

समय अंतराल को कम करने के लिए पीठासीन अधिकारी (पीआरओ) मतदान के दिन हर दो घंटे में नए ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे। (लिंक)

निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी आंकड़ों के तेजी से साझाकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करना। (लिंक)

फॉर्म 17उ और ईवीएम के बीच बेमेल होने की हर स्थिति में वीवीपैट गणना सुनिश्चित की जाएगी। (लिंक)

मतदाता सूचियों की शुद्धता

बिहार में कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण। (लिंक)

लगभग 2 दशकों में पहली बार 4 राज्यों में उपचुनावों से पहले विशेष सारांश पुनरीक्षण। (लिंक)

मृत्यु पंजीकरण आंकड़ों को जोड़ना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ईआरओ को पंजीकृत मौतों की समय पर जानकारी मिले। (लिंक)

विभिन्न व्यक्तियों के लिए समान एढक्ट नंबर (लिंक)

मतदाता सूची में अद्यतन के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई एसओपी, वितरण के प्रत्येक चरण पर एसएमएस सूचना के साथ। (लिंक)

क्षमता निर्माण

पहली बार आईआईआईडीईएम नई दिल्ली में 7,000 से अधिक बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। (लिंक)

बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के लिए पहली बार आईआईआईडीईएम नई दिल्ली में प्रशिक्षण। (लिंक)

कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में कोयला गैसीकरण पर दूसरा रोड शो आयोजित करेगा

(जीएनएस)।

कोयला मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के साथ मिलकर, नई दिल्ली स्थित फिक्की फेडरेशन हाउस में कोयला गैसीकरण यानी सतही एवं भूमिगत प्रौद्योगिकियों पर दूसरा रोड शो आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि और कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह रोड शो मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 13वें दौर के बाद आयोजित किया जा रहा है, जिससे कंपनियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए कोयले का खनन और इस्तेमाल में मदद मिलेगी।

इस आयोजन का उद्देश्य भारत में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों के विस्तार, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त व्यावसायिक मॉडल के विकास और व्यावसायिक स्तर पर स्वदेशी गैसीकरण प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करना है। कोयला गैसीकरण से प्राप्त उत्पादों के विपणन और परियोजनाओं को उनके प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतिगत प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी।

भारत ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और इस रोड शो में रसायन, पेट्रोकेमिकल, तेल एवं गैस, इस्पात, एल्युमीनियम, बिजली, कोयला और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों के साथ-साथ प्रमुख निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के एक साथ आने की उम्मीद है। यह आयोजन उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों और नीति निमार्ताओं को विचारों का आदान-प्रदान करने, निवेश के अवसरों का पता लगाने और देश भर में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए समर्थक रणनीतियों की पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

कोयला गैसीकरण पर दूसरा रोड शो, स्वच्छ, टिकाऊ और आत्मनिर्भर ऊर्जा संबंधी समाधानों की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह कोयला गैसीकरण क्षेत्र में नवाचार, निजी निवेश और सहयोगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

पश्चिम रेलवे द्वारा उधना एवं ब्रह्मपुर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरूआत

मुंबई, अमृत भारत एक्सप्रेस आम आदमी को आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के भारतीय रेल के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ट्रेन तकनीकी रूप से उन्नत है और लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधाओं, बेहतर सुरक्षा और किफायती किराए पर आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। दोनों तरफ पुश-पुल कॉन्फिगरेशन में लगे इंजनों के साथ यह ट्रेन तेज गति, यात्रा समय में कमी और एक सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करती है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

- ट्रेन संख्या 19021/19022 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक):

ट्रेन संख्या 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक रविवार को उधना से 07:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13:55 बजे ब्रह्मपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 5 अक्टूबर, 2025 से चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को ब्रह्मपुर से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 08:45 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 6 अक्टूबर, 2025 से चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, दोंडाइचा, सिंदखेड़ा, अमलनेर, धरणगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुडा, रायगडा, पार्वतीपुरम, बोब्बिली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड और पलासा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 19021 की बुकिंग 26 सितंबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम डेटा का आदान-प्रदान साइबर सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा

दूरसंचार विभाग और एफआईयू-आईएनडी साझेदारी सुरक्षित डिजिटल भुगतानों के लिए धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों का शीघ्र पता लगाने में सहायक है

दूरसंचार विभाग का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म 600 से अधिक हितधारकों के साथ सुरक्षा सहयोग को ओर मजबूत करेगा

(जीएनएस)।

साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दूरसंचार विभाग (डीओटी) और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने आज सूचना साझाकरण और समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन पर दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक (एआई एवं डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट - डीआईयू) श्री संजीव कुमार शर्मा और एफआईयू-भारत के निदेशक श्री अमित मोहन गोविल ने दूरसंचार

सचिव डॉ. नीरज मित्तल और राजस्व सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह समझौता दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (डीआईयू) और देश की शीर्ष वित्तीय खुफिया एजेंसी के बीच सहयोगात्मक खुफिया जानकारी साझा करने के एक नए युग की शुरूआत को दर्शाता है।

इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. नीरज मित्तल ने विभागों में प्रौद्योगिकी बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, विभागों ने अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका भरपूर लाभ उठाया है। हालांकि यह एक जरूरी पहला कदम है, लेकिन सच्ची प्रगति विभागीय सीमाओं से आगे बढ़कर मौजूदा कमियों को दूर करने में निहित है। एक-दूसरे से सीखकर तालमेल विकसित करना बेहद जरूरी है।" डॉ. मित्तल ने आगे कहा, "अगले कदम के रूप में हम एक संयुक्त कार्य समूह के गठन पर विचार कर सकते हैं, जिसमें मुखौटा कंपनियों की पहचान करने और गहन, सहयोगात्मक विश्लेषण और पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।"

राजस्व सचिव श्री अरविंद श्रीवास्तव ने प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता को अधिकतम करने में साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह एक उत्कृष्ट सहयोग है जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे की प्रणालियों को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। इस साझेदारी की प्रौद्योगिकी-संचालित प्रकृति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि यह सटीकता और समयबद्धता के मामले में उच्च दक्षता प्रदान करेगी, जिससे हम डेटा का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएंगे।"

साझेदारी की मुख्य विशेषताएं

उन्नत डेटा साझाकरण तंत्र:

वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) डेटा का वास्तविक समय में साझाकरण, जो वित्तीय धोखाधड़ी के साथ उनके संबंध के आधार पर मोबाइल नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है।

दूरसंचार विभाग मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (एमएनआरएल) डेटा को, जिसमें ऐसे डिस्कनेक्शन की तारीख और कारण भी शामिल होगा, स्वचालित आधार पर एफआईयू-आईएनडी के साथ साझा करेगा।

एफआईयू-आईएन साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल गतिविधियों से संबंधित संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में शामिल खातों से जुड़े

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' के अंतर्गत 'श्रमदान' का आयोजन

मुंबई, 25 सितंबर, 2025

'एक राष्ट्र - एक घंटा - स्वच्छ भारत के लिए एक साथ!'

स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत 25 सितंबर 2025 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' थीम के अंतर्गत एक बृहत श्रमदान गतिविधि का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस पहल में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (आरई) श्री रामेंद्र कुमार तिवारी, पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार, पश्चिम रेलवे मुख्यालय और मुंबई सेंट्रल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्यालय, मंडल और मुंबई सेंट्रल स्टेशन के कर्मचारियों, साथ ही स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

और एक स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक पर्यावरण के लिए एकजुटता की भावना का प्रदर्शन किया। इस अभियान में स्टेशन के सबसे व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हिस्सों में से एक, पार्सल कार्यालय क्षेत्र में व्यापक सफाई गतिविधियाँ शामिल थीं, जिससे भारतीय रेल के स्वच्छ और यात्री-अनुकूल परिसर प्रदान करने के मिशन को बल मिला।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, श्रमदान अभियान केवल सफाई गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाला एक समग्र अभियान था। पार्सल कार्यालय क्षेत्र में गहन सफाई अभियान में 50 से अधिक रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। लोअर परेल वर्कशॉप की रेलवे सांस्कृतिक टीम द्वारा मुख्य प्रतीक्षालय में प्रस्तुत एक मनमोहक नुक्कड़ नाटक ने 120 से अधिक यात्रियों को आकर्षित किया, जिसमें स्वच्छता, अपशिष्ट पृथक्करण और व्यवहार परिवर्तन का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में, मुंबई सेंट्रल के सकुर्लेटिंग गार्डन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (आरई) श्री रामेंद्र कुमार तिवारी और पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने पौधे लगाए।

यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के प्रति पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है तथा स्वच्छ, हरित एवं सौंदर्यपरक रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र के

एक दिन एक घंटा एक साथः भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रव्यापी श्रमदान किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उसके कई सार्वजनिक उपक्रमों/ संबद्ध/ अधीनस्थ अधिकारियों ने 25 सितंबर, 2025 को सुबह 8 बजे पूरे देश में "एक दिन एक घंटा एक साथ" कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता गतिविधियों के साथ एक और उपलब्धि हासिल की।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने "एक दिन, एक घंटा, एक साथः स्वच्छता ही सेवा 2025" अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी श्रमदान के अंतर्गत नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित हनुमान मंदिर के बाहरी परिसर में सफाई अभियान चलाया। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अभियान में बड़े पैमाने पर उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना, सफाई व्यवस्था में सुधार लाना और आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट के उचित निपटान के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अपने एक घंटे के सामूहिक श्रमदान से विभाग के कर्मचारियों ने एक स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त भारत सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त, विभाग के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/ अधीनस्थ कार्यालयों की ओर से अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं।

हापुड़ स्थित भारतीय अनाज प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई) ने हापुड़ बस डिपो पर स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि लुधियाना स्थित आईजीएमआरआई ने आईएसबीटी, लुधियाना में इस अभियान को चलाया।

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) की टीम ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान - "एक दिन, एक साथ, एक घंटा" में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामुदायिक कल्याण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। मयूर विहार स्थित आरडब्ल्यूए पार्क में श्रमदान किया गया। इस अवसर पर एक अत्यंत प्रेरित टीम ने ऊर्जा, उत्साह और सच्ची टीम भावना के साथ एकजुट होकर सार्वजनिक स्थल की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक घंटा समर्पित किया।

भावनगर मंडल में रेलवे एवं एनडीआरएफ टीम द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनस स्टेशन यार्ड में रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप 25 सितम्बर, 2025 (गुरुवार) को रेलवे एवं एनडीआरएफ (वडोदरा) टीम के संयुक्त प्रयास से आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने हेतु एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आयोजित इस मॉक ड्रिल में शंटिंग के दौरान यात्री कोच के दूसरे कोच से टकराने एवं उसमें आग लगने की काल्पनिक स्थिति का सृजन किया गया। इस दौरान घायल यात्रियों को कोच से निकालकर उन्हें अस्पताल पहुँचाने का अभ्यास किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 10.00 बजे सूचना प्राप्त होते ही ओन-ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक द्वारा कंट्रोल सहित

अन्य विभागों को सतर्क किया गया। तत्काल एम्बुलेंस, दुर्घटना राहत ट्रेन एवं अन्य आवश्यक संसाधन घटनास्थल पर बुलाए गए। वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री सोनू कुमार के दिशा-निर्देश में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त रूप से बचाव एवं राहत कार्य को अंजाम दिया। इस दौरान राज्य सरकार की 6 एम्बुलेंस, रेलवे अस्पताल की 1 एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड का एक वाहन भी सक्रिय रूप से शामिल रहा। एनडीआरएफ-6 बटालियन (वडोदरा) के कमांडेंट द्वारा मौके पर दल को बचाव कार्य की बारीकियों एवं आवश्यक सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया।

इस मॉक ड्रिल में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं ओपरेटिंग, टेलिकॉम, सिग्नल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, मेडिकल, कर्षण, रेल सुरक्षा बल, कोचिंग डिपो, वाणिज्य, लोकोमोटिव तथा सेफ्टी विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस आयोजन में एनडीआरएफ-6 बटालियन (वडोदरा) के 40 सदस्यों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। लगभग 250 से अधिक सदस्यों की भागीदारी के साथ संपन्न इस मॉक ड्रिल ने रेलवे एवं आपदा प्रबंधन दल की तत्परता और समन्वय का प्रभावी प्रदर्शन किया।

भावनगर मंडल एक बार फिर बना भारतीय रेलवे का अग्रणी मंडल - 5996 कर्मचारियों को आदेश जारी होने के दो घंटे के भीतर किया बोनस का भुगतान

भावनगर मंडल ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और तत्परता का परिचय देते हुए वर्ष 2024-25 के लिए घोषित प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस (ढछइ) के अंतर्गत मंडल ने अपने 5996 ग्रुप 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के कर्मचारियों को कुल रु.10,48,99,048/- (दस करोड़ अड़तालीस लाख निन्यानवे हजार अड़तालीस रुपये) का भुगतान एक साथ कर गौरव प्राप्त किया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2025 को रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की गई थी। संबंधित सर्कुलर रेल मंत्रालय द्वारा सायं 7:00 बजे जारी किया गया। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन के नेतृत्व में सैलरी बिल अनुभाग एवं वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री मोहित पंचाल के नेतृत्व में अकाउंट्स विभाग की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बोनस की संपूर्ण राशि को प्रोसेस कर बैंक को उसी दिन 20.00 बजे भुगतान हेतु भेज दिया, जिससे सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में राशि दिनांक 24/09/2025 को ही 21.00 बजे क्रेडिट कर दी गई।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी भावनगर मंडल ने बोनस भुगतान के मामले में भारतीय रेल का पहला मंडल बनने की उपलब्धि हासिल की थी। जिसके लिए संबंधित अनुभाग के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया था।

भावनगर मंडल की इस उपलब्धि के लिए श्री दिनेश वर्मा, मंडल रेल प्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों के कल्याण और संतोष के प्रति मंडल की इस प्रतिबद्धता एवं समर्पित कार्य की सराहना की है।

भावनगर रेलवे मंडल के 9 स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली के समय में परिवर्तन

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल के 9 स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली (ढफ्र) काउंटर के समय में परिवर्तन किया गया है। यह नई व्यवस्था आगामी 01 अक्टूबर, 2025 (बुधवार) से प्रभावी होगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नई समय-सारणी से यात्रियों को आरक्षण टिकट प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

1. जोरावरनगर स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 14.00 बजे से 18.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।

2. वढ़वाण सीटी स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 13.00 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 15.00 बजे से 19.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 13.00 बजे तक रहेगा।

3. लींबडी स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 16.00 बजे से 19.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।

4. मालीया हाटीना स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय शाम 17.00 बजे से 18.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।

5. जेतलसर स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 11.30 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय दोपहर 16.30 बजे से 18.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से 11.30 बजे तक रहेगा।

6. दामनगर स्टेशन पर सोमवार से शनिवार दो पालियों में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। पहली पाली का समय सुबह 08.00 बजे से 11.30 बजे तक तथा दूसरी पाली का समय शाम 17.30 बजे से 19.00 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन आरक्षण सेवा का समय सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक रहेगा।

7. विरपुर स्टेशन पर प्रतिदिन केवल एक पाली में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। इसका समय प्रतिदिन सुबह 08.00 बजे से दोपहर 14.00 बजे तक रहेगा।

8. सासण गीर स्टेशन पर प्रतिदिन केवल एक पाली में आरक्षण सेवा कार्यरत होगी। इसका समय प्रतिदिन सुबह 08.00 बजे से दोपहर 14.00 बजे तक रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नवरात्रि के चौथे दिन अहमदाबाद में नगरदेवी श्री भद्रकाली माताजी के दर्शन कर स्वच्छता अभियान के तहत महा श्रमदान में शामिल हुए

गांधीनगर, 25 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गुरुवार को अहमदाबाद की नगर देवी श्री भद्रकाली माताजी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत आयोजित किए गए महा श्रमदान में सहभागी हुए और भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में साफ-सफाई की।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर-2025 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत राज्य में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का आयोजन किया गया है।

स्वच्छता ही सेवा-2025 अभियान के अंतर्गत अब तक अहमदाबाद शहर में 2.97 लाख से

अधिक नागरिक स्वैच्छिक रूप से स्वच्छता की गतिविधियों में शामिल हुए हैं। अभियान के तहत 1877 मीट्रिक टन से अधिक कूड़ा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया गया है। इसके अलावा, शहर की लगभग 5495 मुख्य सड़कों, 3677 वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा 3229 से अधिक रिहायशी इलाकों की साफ-सफाई भी शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने भद्रकाली मंदिर क्षेत्र में सफाई श्रमदान के दौरान राहे खेर गर्ल्स हाईस्कूल, खमासा की छात्राओं से मुलाकात की और उनके द्वारा स्वच्छता पर तैयार किए गए चित्रों का अवलोकन किया। उन्होंने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश इसी प्रकार जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर अनुपम ब्रिज के पास उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, स्थानीय विधायक सर्वश्री अमितभाई ठाकर, कौशिकभाई जैन, अमूलभआई भट्ट, श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, दिनेशभाई कुशवाह, जीतूभाई पटेल, शहर के अग्रणी श्री प्रेरकभाई शाह और श्री भूषणभाई भट्ट, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी और अधिकारियों सहित नागरिक उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो को संबोधित किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन करते हुए इस मेले में भाग लेने वाले सभी व्यापारियों, निवेशकों, उद्यमियों और युवा प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस आयोजन में 2,200 से अधिक प्रदर्शक अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि इस बार के व्यापार शो में रूस भागीदार देश है और यह समय की कसौटी पर खरी उतरी साझेदारी को और मजबूत बनाता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के सहयोगियों और अन्य हितधारकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शो का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने राष्ट्र को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के

उत्थान के लिए अंत्योदय के पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि विकास सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे और सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करे। उन्होंने कहा कि भारत अब समावेशी विकास का यही मॉडल दुनिया में प्रस्तुत कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण देते हुए भारत के फिनटेक क्षेत्र की वैश्विक मान्यता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समावेशी विकास में इसका योगदान है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सभी को साथ लेकर चलने वाले यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर और ओएनडीसी जैसे खुले मंच तैयार किए हैं और यह सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने "सबके लिए मंच, सबकी प्रगति" के सिद्धांत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन मंचों का प्रभाव पूरे भारत में दिखाई दे रहा है, जहां मॉल में खरीदारी करने वाले और सड़क किनारे चाय बेचने वाले, दोनों ही यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि औपचारिक ऋण, जो कभी केवल बड़ी कंपनियों के लिए सुलभ था, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी-पटरी वालों तक पहुंच रहा है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) को एक और परिवर्तनकारी उदाहरण बताते हुए श्री मोदी ने याद दिलाया कि एक समय था जब सरकार को सामान बेचना केवल बड़े व्यापारियों तक ही सीमित था। आज, लगभग 25 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता जेम पोर्टल से जुड़े हैं।

'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' थीम के साथ राज्य सरकार का 12वां वार्षिक चिंतन शिविर 13 से 15 नवंबर तक वलसाड जिले में स्थित श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आयोजित होगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में चिंतन शिविर के आयोजन की रूपरेखा तय की गई

शिविर में हिस्सा लेने के लिए ट्रेन से वलसाड जाएंगे मंत्रीगण और वरिष्ठ सचिव

चिंतन शिविर में पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और विविधीकरण, विकसित गुजरात के लिए क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा और पर्यावरण सहित विभिन्न विषय होंगे शामिल

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रशासनिक कार्य संस्कृति को समय के अनुरूप नया मोड़ देने के लिए 2003 से शुरू किए गए चिंतन शिविर का 12वां संस्करण इस वर्ष मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आयोजित होगा

गांधीनगर, 25 सितंबर : राज्य सरकार का 12वां वार्षिक चिंतन शिविर आगामी 13 से 15 नवंबर, 2025 के दौरान वलसाड जिले के धरमपुर के निकट श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आयोजित होगा। इस शिविर में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ सचिव और प्रशासनिक अधिकारी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को गांधीनगर में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस वार्षिक चिंतन शिविर के आयोजन की रूपरेखा तय की गई।

बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राज्य सरकार के प्रशासन को अधिक जनाभिमुख और जनहित-केंद्रित बनाकर ईज ऑफ गवर्नेंस की कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए 2003 में सामूहिक वार्षिक चिंतन शिविर की शुरूआत की थी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए प्रसासनिक व्यवस्था को समयानुरूप टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के साथ ही संवेदनशीलता की नई दिशा देते हुए इस वर्ष 12वें वार्षिक चिंतन शिविर का आयोजन किया है।

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण प्रभाग की ओर से आयोजित होने वाला 12वां वार्षिक चिंतन शिविर 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' की स्थायी थीम के साथ आयोजित होगा।

इस वर्ष के चिंतन शिविर में सामूहिक चिंतन-मंथन के लिए जिन विषयों की सूची तैयार की गई है, उसमें पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र की वृद्धि और विविधीकरण, विकसित गुजरात के लिए क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा, हरित ऊर्जा और पर्यावरण आदि विषयों को शामिल किया गया है।

इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान ट्रैकिंग, साइकिलिंग, एडवांस मेडिटेशन योग जैसी गतिविधियां तथा रात्रि के दौरान विभिन्न खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी विचार चल रहा है।

इस शिविर में भाग लेने वाले शिविरार्थी समूह में वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर 13 नवंबर को वलसाड पहुंचेंगे और शिविर पूरा होने के बाद भी ट्रेन के जरिए ही वापस अहमदाबाद लौटेंगे।

शिविर का प्रारंभ 13 नवंबर को दोपहर उद्घाटन सत्र के साथ होगा तथा बाकी के दो दिनों में पूरे दिन के दौरान विभिन्न चर्चा सत्र, समूह चर्चा बैठकें आयोजित की जाएंगी जिसमें विषय विशेषज्ञ वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित होंगे।

12वें चिंतन शिविर के सर्वग्राही आयोजन की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुनयना तोमर, मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह और सचिव डॉ. विक्रांत पांडे तथा प्रशासनिक सुधार प्रभाग के सचिव सहित कई अन्य वरिष्ठ सचिव मौजूद रहे।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए एमके1ए विमानों की खरीद के लिए एचएएल के साथ 62,370 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2025 को 62,370 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) से अधिक की लागत से लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन विमानों की डिलीवरी 2027-28 के दौरान शुरू होगी और छह साल की

भारतीय वायु सेना के लिए 68 लड़ाकू विमानों और 29 ट्विन सीटर सहित 97 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) एमके1ए और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स अवधि में पूरी हो जाएगी।

विमान में 64 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें जनवरी 2021 में हस्ताक्षरित पिछले एलसीए एमके1ए अनुबंध के अलावा 67 अतिरिक्त आइटम शामिल किए जाएंगे। उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (एईएसए) रडार, स्वयं रक्षा कवच और कंट्रोल सरफेस एक्ट्यूएटर्स जैसी उन्नत स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों का एकीकरण, आत्मनिर्भरता पहल को और मजबूत करेगा।

इस परियोजना को लगभग 105 भारतीय कंपनियों के एक मजबूत विक्रेता आधार द्वारा समर्थित किया जा रहा है जो विस्तृत घटकों के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। इस उत्पादन से छह वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष लगभग 11,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू एयरोस्पेस इको-सिस्टम को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा मंत्री ने 'स्वच्छोत्सव 2025' के तहत विशेष स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया और सफाई दौड़ को हरी झंडी दिखाई, स्वयंसेवकों को सम्मानित किया

सेना मुख्यालय में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' अभियान का आयोजन; रक्षा मंत्री ने युवाओं और सशस्त्र बलों की सक्रिय भागीदारी को रेखांकित करते हुए स्वच्छ एवं हरित भारत के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया

"स्वच्छता केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है, जो अनुशासन और उत्तरदायित्व का प्रतीक है" - रक्षा मंत्री

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर, 2025 को सेना मुख्यालय यूनिट रन कैंटीन में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' नामक विशेष स्वच्छता पहल का नेतृत्व किया। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक रक्षा मंत्रालय में आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत स्वच्छोत्सव 2025 का हिस्सा था। इस अवसर पर स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में सामूहिक प्रयासों की शक्ति पर बल दिया गया। इस वर्ष का विषय राष्ट्र की उत्सव भावना को प्रतिबिंबित करते हुए स्वच्छ भारत के संकल्प को और सुदृढ़ करता है।

श्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए 'स्वच्छता संकल्प' लिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले सफाई मित्रों को सम्मानित किया और

पर्यावरण-अनुकूल, शून्य अपशिष्ट वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु वृक्षारोपण भी किया। रक्षा मंत्री ने प्रतीकात्मक भाव प्रदर्शन के रूप में 100 एनसीसी कैडेटों के साथ स्वच्छता दौड़ को हरी झंडी दिखाई, जिससे स्वच्छ भारत अभियान को गति देने में युवाओं की सक्रिय भूमिका पर बल दिया गया।

रक्षा मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल साफ-सफाई का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है, जो अनुशासन व जिम्मेदारी का परिचायक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है, जबकि अस्वच्छता बीमारियों तथा नकारात्मकता का कारण बनती है। श्री सिंह ने भारत की परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता को सदैव सभ्य और सुसंस्कृत समाज की पहचान माना गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सितंबर-2025 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' में जनशिकायतों का निपटारा किया

मुख्यमंत्री के संवेदनशील निर्णय से 94 वर्षीय वृद्धा को मिला त्वरित न्याय

सरकार सदैव बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ खड़ी रहेगी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

सितंबर-2025 के जिला 'स्वागत' में 1321 और तालुका 'स्वागत' में प्राप्त 2616 शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू

गांधीनगर, 25 सितंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2003 में शुरू की गई पहल- राज्य 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष पहुंचाने के साथ-साथ उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों की समस्याओं को सदैव प्राथमिकता देकर उनके त्वरित निवारण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इसका एक और उदाहरण सितंबर महीने के राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में देखने को मिला।

इस कार्यक्रम के दौरान एक 94 वर्षीय वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री के समक्ष उसे देय भरण-पोषण की राशि के संबंध में अभ्यावेदन पेश किया था। वृद्ध महिला की वेदना भरी आपबीती को सुनकर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए तत्काल संबंधित जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस वृद्ध महिला को अविलंब भरण-पोषण की राशि दिलवाई जाए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी स्पष्ट किया कि सरकार प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। विशेषकर, हमारे वरिष्ठ नागरिक समाज का गौरव हैं और राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर है।

उन्होंने आगे जिला स्तर के अधिकारियों को जनसामान्य की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने तथा वंचित, पीड़ित और वृद्ध नागरिकों के अभ्यावेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने वलसाड जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि जिले के 7 किसानों को खेतों की पैमाइश और अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर उचित न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने वलसाड जिले के 7 किसानों को उनके खेतों की पैमाइश और अधिग्रहण के मुआवजे के संबंध में उचित न्याय दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के जिला कलेक्टर को निर्देश देकर किसानों के प्रति संवेदना का भी उदाहरण प्रस्तुत किया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने तथा भूमि पैमाइश के मुद्दों के संबंध में नागरिकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कार्रवाई करने के भी आवश्यक निर्देश दिए।

25 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम में पूरे राज्य से 115 से अधिक आवेदक उपस्थित रहे, जिनमें से 14 आवेदकों को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सुना। इसके अलावा, शेष अभ्यावेदनों के संबंध में संबंधित विभागों तथा जिला स्तर के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

राज्य सरकार द्वारा पूरे सितंबर महीने के दौरान जिला स्तर पर आयोजित 'स्वागत' कार्यक्रमों में प्राप्त 1321 और तालुका स्तर पर आयोजित 'स्वागत' कार्यक्रमों में प्राप्त 2616 अभ्यावेदनों के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (सीईओ) श्री धीरज पारेख एवं श्री राकेश व्यास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का नेतृत्व किया, एआरएसडी कॉलेज में श्रमदान में भाग लिया

(जीएनएस)।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत श्रमदान में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के आ'ान से प्रेरित होकर वर्तमान में जारी स्वच्छोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता का अभ्यास केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना देना चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छता को अपनी आदत बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए

एक उज्ज्वल, स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में हाथ मिलाने का आग्रह किया।

छात्रों के साथ बातचीत के दौरान, श्री प्रधान ने कहा कि युवा मन के साथ जुड़ना हमेशा प्रेरणादायक होता है, क्योंकि उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनका उत्साह और आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने स्वच्छता सुनिश्चित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, विकसित भारत के विजन में उनकी प्राथमिकता, जीवन और करियर में अनुशासन के महत्व और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों से प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक घंटा स्वच्छता के लिए समर्पित करने का आग्रह किया।

मंत्री ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के आ'ान को भी याद किया। उन्होंने युवा पीढ़ी से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, स्थानीय के लिए मुखर (वोकल फॉर लोकल) होने और विकसित राष्ट्र के विजन की ओर अग्रसर भारत की नई विकास गाथा लिखने में योगदान देने की अपील की।

इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई) के सचिव डॉ. विनीत जोशी; दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह; संयुक्त सचिव (डीओएचई) श्री सैयद एकराम रिजवी; संयुक्त सचिव (डीओएचई) श्रीमती रीना सोनोवाल कौली; संयुक्त सचिव (डीओएचई) श्री आर्मस्ट्रांग पामे; मंत्रालय के अधिकारी तथा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा और अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने स्वच्छोत्सव- स्वच्छता ही सेवा 2025 के तहत 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ, राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक श्रमदान' गतिविधि में भाग लिया

(जीएनएस)।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्वच्छता उत्सव - स्वच्छता ही सेवा 2025 के एक भाग के रूप में, 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय संख्या 2, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली के पास, एपीएस कॉलोनी में 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' अभियान की थीम के अंतर्गत एक घंटे का स्वच्छता श्रमदान आयोजित किया। इस श्रमदान का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सचिव श्री संजय कुमार ने किया। स्वच्छोत्सव में वरिष्ठ अधिकारियों, छात्रों और शिक्षकों सहित 200 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

श्रमदान में सक्रिय रूप से शामिल होने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में श्री

धीरज साहू, अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सुश्री प्राची पांडे, आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन और संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सुश्री अर्चना शर्मा अवस्थी, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और डॉ. अमरप्रीत दुग्गल, संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी शामिल थे। यह पहल 'स्वच्छोत्सव' की भावना को दर्शाती है और इस संदेश को पुष्ट करती है कि स्वच्छता तभी सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है जब छात्र, शिक्षक और संस्थान एकजुट होकर कार्य करें।

17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक मनाए जा रहे "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के अंतर्गत, देश भर के स्कूली छात्र स्वच्छता शपथ, सफाई अभियान, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएँ, जागरूकता रैलियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वृक्षारोपण अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। अभियान

डीआरडीओ ने रेल आधारित मोबाइल लांचर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया

(जीएनएस)।

डीआरडीओ ने सामरिक बल कमान (एसएफसी) के सहयोग से 24 सितंबर 2025 को पूर्ण परिचालन परिदृश्य के अंतर्गत रेल आधारित मोबाइल लांचर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। 2000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए डिजाइन की गई अगली पीढ़ी की यह मिसाइल विभिन्न उन्नत सुविधाओं से लैस है।

अपनी तरह के इस पहले प्रक्षेपण को विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया और यह रेल नेटवर्क से बिना किसी बाधा के प्रक्षेपित की जा सकती है। यह मिसाइल देश भर में गतिशीलता प्रदान करने के साथ-साथ कम दृश्यता के साथ-साथ कम प्रतिक्रिया समय में भी प्रक्षेपण करने की क्षमता रखती है। यह आत्मनिर्भर है और अत्याधुनिक संचार प्रणालियों और सुरक्षा तंत्रों सहित सभी स्वतंत्र प्रक्षेपण क्षमता सुविधाओं से सुसज्जित है।

मिसाइल के प्रक्षेप पथ की विभिन्न ग्राउंड स्टेशनों से निगरानी की गई और इस प्रक्षेपण ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। इस सफल